limited quantities of defence stores on a very selective basis. The Defence Export Promotion Board has been in existence since 1982 primarily to administer this limited export effort and adequate precautions are taken to ensure that Indian defence stores do not reach undesirable hands.

Evasion of Excise Duty by Industrial Units

1130. SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether large industrial units are mainly responsible for evasion of excise duties;

(b) whether they are demanding moratorium of deferred payment of excise duties; and

(c) how Government propose to recover the huge arrears ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : (a) It would not be correct to generalise that large industrial units are mainly responsible for evasion of excise duties.

(b) Some of the large industrial units have requested for deferred payment of excise duty arrears arising out of judicial pronouncements.

(c) Recovery of arrears of Central excise duty is an on-going function. Such measures (administrative, legal and others aimed at realising the arrears) as are considered necessary from time to time continue to be taken. These measures include steps to expedite the finalisation of the cases, in Courts or before quasi-judicial bodies, of disputed demands where recoveries had been stayed and enforcing through persuasive or coercive action, the demands that are not in dispute.

काली सूची में शामिल की गई कम्पनियों को नए ठेके

1131. श्री जगपाल सिंह :
श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री भीम सिंह :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :
क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1984 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में 'काली सूची कम्पनियों को नए ठेके' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो काली सूची में शामिल 26 कम्पनियों के नाम क्या है ;

(ग) इन कम्पनियों में की गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्य- की गई है;

(घ) क्या सरकार अनियमितताओं के इन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता विभाग के माध्यम से जांच करवाएगी; और

(ङ) क्या अगला टेंडर कुछ कम्पनियों को दिया जायेगा और नई कम्पनियों को ठेके देने की मुख्य शर्तें क्या होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) 26 कम्पनियाँ, जो वर्ष 1982-83 में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ जी० आई० पाइपों* की सप्लाई के लिए दर ठेके पर थीं, उन्हें सरकार द्वारा काली सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) 27 मई, 1983 के 'इकनौमिक टाइम्स' में एक बयान प्रकाशित हुआ था, जो कि टिस्को के श्री रूसी मोदी द्वारा कथित माना जाता है, उसमें यह लिखा था कि दर ठेके प्राप्त फर्मों ने अपने उत्पादों को, प्राइवेट पार्टियों को, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर-ठेका मूल्यों से कम दरों में बेचा है। इसकी जाँच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निवेदन किया गया है। अनियमितताओं आदि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विवरणों के बारे में तभी ज्ञात होगा, जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ङ) वर्ष 1983-84 के लिए जी० आई० पाइपों के नए दर ठेके/मूल्य करार, पाँच फर्मों को दिए गए, इनमें से तीन फर्में नई हैं, जिनकी क्षमता और समर्थता को सरकारी ठेकों के लिए सन्तोषजनक माना गया था। दर ठेका/मूल्य करार प्राप्त इन पाँच फर्मों की पूर्ण क्षमता, जी० आई० पाइपों* की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए टेंडर मांगे गए थे और उन पर विचार किया जा रहा है। इसकी शर्तें ये होंगी कि उन फर्मों की इसके लिए क्षमता और समर्थता होनी चाहिए, उनके मूल्य उचित होने चाहिएं तथा सरकार के हितों की रक्षा भी हो, और इन फर्मों द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के मानक दर ठेके की शर्तों को स्वीकार किया जाए।

*जी०आई० पाइप--गल्वैनाइज्ड आयरन पाइप

100 रुपए के मूल्य के जाली करेंसी नोट

1132. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री शिवशरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1984 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में 'सौ-सौ' के जाली नोट-शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन नोटों को किन-किन स्थानों से बरामद किया गया और 31 जनवरी, 1984 तक, विगत एक वर्ष के दौरान, कुल कितने रुपये के जाली नोट पकड़े गए हैं; और

(ग) इस प्रकार के अपराधों में शामिल कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है और इसमें कोई बड़ा तस्कर गिरोह सक्रिय है, यदि हां तो उनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी. हाँ।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न भागों में 31.1.84 तक समाप्त हुए पिछले एक वर्ष के दौरान पकड़े गए उन जाली करेंसी नोटों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है जिनकी रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दी गई है।

मूल्य वर्ग	बरामद किए गए जाली करेंसी नोट जिनमें जब्त किए गए नोट शामिल हैं
100 रुपए	13,728
50 रुपए	407
20 रुपए	509
10 रुपए	2,664
5 रुपए	51
2 रुपए	160
1 रुपए	32

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 236 है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ये